राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की बैठक में हुए कई निर्णय

42 माह में तैयार होगा कोचिंग हब, सात मंजिल के आठ टावर बनेंगे

फॉलोअप

शहर के सभी कोचिंग सेंटर होंगे एक जगह, तैयारी शुरू

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर

- कोचिंग हब में 231 करोड़ और सिटी पार्क में खर्च होंगे 70 करोड़ रुपए,
- राज्य के 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाओं में बनेंगे 12 हजार से अधिक आवास

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजस्थान अवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक बुधवार को मुख्यालय में हुई। इसमें कई योजनाओं पर मुहर लगी। राज्य का पहला कोचिंग हब 68 हजार वर्गमीटर में प्रताप नगर में बनेगा। इसका निर्माण दो चरणों में पूरा होगा। कोचिंग हब में सात मंजिल के आठ सांस्थानिक टावर बनेंगे। पहले चरण में पांच और दूसरे चरण में तीन टावर बनाए जाएंगे। एक लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में मंडल 231 करोड़ रुपए खर्च करेगा। निर्माण के बाद कोचिंग संस्थानों को प्रत्येक निर्मित मंजिल बेची जाएगी। 70 हजार छात्र एक कैम्पस में पढ़ सकेंगे। राजस्व के रूप में मंडल को 416 करोड़ रुपए मिलेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि हब में 50 हजार वर्गफीट क्षेत्र में सात मंजिला लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया जाएगा। वहीं, 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी बनेगा। छात्रों को रहने के लिए 1100-1100 वर्गमीटर के हॉस्टल व पीजी के लिए चार भूखंड विकसित किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट 42 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद कोचिंग सेन्टर्स को आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राजस्थान अवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक में मौजूद अधिकारी।

सिटी पार्क में खर्च होंगे ₹70 करोड़

मानसरोवर आवासीय योजना में निर्मित होने वाले सिटी पार्क पर लगभग 70 करोड़ रूपए खर्च होंगे। यह पार्क 18 हैक्टेयर क्षेत्र में 75 फीसदी ग्रीन एरिया के साथ विकसित किया जाएगा, जो कि सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। मध्यम मार्ग और न्यू सांगानेर रोड पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। पार्क में वॉक वे, जॉगिंग ट्रेक, पार्किंग ब्लॉक, एंट्रेंस प्लाजा, वाटर बॉडीज, बॉटनीकल गार्डन और बच्चो के खेलने के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा। इसी बरसात में पौधरोपण किया जाएगा।

लॉन्च होंगी 21 आवासीय योजनाएं

राज्य के 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इनमें 12,351 आवास बनेंगे। इसके साथ ही जयपुर स्थित पांच योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 2652 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, इंदिरा गांधी नगर विस्तार, टोंक के निवाई, उदयपुर के सविना खेड़ा, दक्षिण विस्तार, देवाली, भिण्डर, आबूरोड, सहित अन्य शहरों में योजनाएं आएंगी

ये निर्णय भी हुए

- मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित किया जाएगा। पहले आवासीय आरक्षित दर के दोगुना पर आवंटन किया जाता था। इस फैसले से मंडल को 100 करोड़ रुपए की आय होगी। अब तक इस पर सिर्फ पौधरोपरण ही किया जा सकता था, लेकिन अब निर्माण भी किया जा सकेगा।
- मासिक किश्तें, आवंटन, नीलामी और ओसीएस की शेष राशि बिना ब्याज के 30 सितम्बर तक जमा करा सकेंगे।
- नीलामी या सांस्थानिक भूखंडों के आवंटन के मामलों में राशि चुकाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। पहले आवंटन जारी होने के 60 दिन में सम्पूर्ण राशि चुकानी होती थी। अब 180 दिन में राशि चुका सकेंगे।
- अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया है। शाखा में पुलिस से कार्मिक लगाए जाएंगे। मुख्यालय स्तर पर एक पुलिस उप अधीक्षक सहित अन्य जवान तैनात होंगे।

दो नकबजन गिरफ्तार

युवक गिरफ्तार